

करेंट अफेयर्स बिहार (संग्रह)



जून
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना	3
संपूर्ण क्रांति की 50 वीं वर्षगांठ.....	4
बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन (संशोधन) नीति, 2025	5
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)	6
बिहार ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य.....	7
साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025	8
बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र	10
बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण कल्याण पहल को मंजूरी दी	12

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



SCAN ME

UPSC
क्लासरूम
कोर्सस



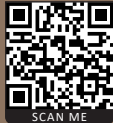
SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



SCAN ME

दृष्टि लर्निंग
ऐप



SCAN ME

बिहार

कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना

चर्चा में क्यों ?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना ज़िले में बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया।

- यह पहल राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन (JJHM) का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिये नवीकरणीय और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य बिंदु

- परियोजना के बारे में:
 - सौर ऊर्जा परियोजना पटना के बिक्रम में मुख्य नहर के 2 किमी. क्षेत्र में स्थित है।
 - इसकी स्थापित क्षमता 2 मेगावाट है और यह जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5.7 एकड़ भूमि पर बनी है।
 - यह परियोजना RESCO (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के तहत विकसित की गई है, जहाँ एक निजी फर्म (तीसरा पक्ष) प्रणाली को स्थापित, संचालित और रखरखाव करती है।

जल-जीवन-हरियाली मिशन (JJHM)

- परिचय
 - JJHM एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करता है।
 - वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, यह जलवायु स्थिरता और संसाधन संरक्षण के लिये एक बहु-हितधारक पहल के रूप में राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।
 - ग्रामीण विकास विभाग इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय के साथ नोडल विभाग की भूमिका निभाता है।
 - इसका आदर्श वाक्य है: “जल, जीवन और हरियाली – तभी होगी समृद्धि”।
- उद्देश्य और लक्षित क्षेत्र:
 - यह मिशन जलवायु स्थिरता, जल संरक्षण, प्रदूषण-मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु-लचीली कृषि को प्रोत्साहित करता है।
 - यह नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक जलवायु जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।
 - JJHM, नागरिकों को स्थायी पारिस्थितिक प्रभाव के लिये लक्षित, समयबद्ध कार्यों के माध्यम से हरित भविष्य का निर्माण करने के लिये सशक्त बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ प्रमुख घटक (11 सूत्री एजेंडा):

- ❶ सार्वजनिक जल संरचनाओं की मरम्मत
- ❷ तालाबों/झीलों/कुओं/बावड़ियों का सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार
- ❸ सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार
- ❹ नहरों/धाराओं के पास कुएँ/चेक डैम बनाना
- ❺ छोटी नदियों/पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम बनाना
- ❻ अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना
- ❼ वर्षा जल संचयन संरचनाएँ बनाना
- ❽ पशुओं के पीने के पानी में सुधार करना
- ❾ वैकल्पिक फसलों और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना
- ❿ सौर ऊर्जा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना
- ⓫ जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान

संपूर्ण क्रांति की 50 वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान की 50 वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

मुख्य बिंदु

❖ संपूर्ण क्रांति के बारे में:

- ❶ प्रारंभ: 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान, पटना में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।
- ❷ उद्देश्य: वर्ष 1974 के इस आंदोलन का उद्देश्य भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उत्पीड़न को दूर करने के लिये सामाजिक सुधार की माँग करना था।
- ❸ प्रभाव: 1970 के दशक में इस आंदोलन ने सत्ताधारी व्यवस्था को चुनौती देने हेतु विभिन्न विपक्षी समूहों को एक मंच पर लाने का कार्य किया।
- ❹ गैर-चुनावी दृष्टिकोण और जन आंदोलनों ने भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों और कार्यों को आकार दिया।
- ❺ संपूर्ण क्रांति ने एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन को प्रेरित किया, जो दिल्ली तक फैल गया और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया।
- ❻ इस आंदोलन से उत्पन्न हुई अशांति ने वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा में योगदान दिया।

जयप्रकाश नारायण

- ❖ लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध, जयप्रकाश नारायण एक क्रांतिकारी, राजनीतिक चिंतक तथा जननेता थे।
- ❖ उनका जन्म 11 अक्तूबर 1902 को सिताबदियारा, बिहार में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के प्रमुख नेता रहे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ प्रारंभ में माक्सवाद से प्रभावित होने के बाद, उन्होंने गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा को अपनाया, जिसमें अहिंसा, ग्राम स्वराज (गाँव आधारित आत्मनिर्भरता) तथा सामाजिक सुधारों पर विशेष जोर था।
- ❖ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसे समाजवादी संगठनों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ❖ मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण ने राममनोहर लोहिया, फूलैना प्रसाद वर्मा, सुराज नारायण सिंह और योगेन्द्र शुक्ल जैसे नेताओं के साथ मिलकर नेपाल के तराई क्षेत्र के राजविलास वन में 'आज़ाद दस्ता' का गठन किया।
- ❖ आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी गुरिल्ला संगठन था, जिसका उद्देश्य था—
 - ब्रिटिश प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर उनकी सत्ता को कमजोर करना,
 - तार और रेलवे जैसी संचार प्रणालियों को नष्ट कर ब्रिटिश ढाँचे को बाधित करना,
 - ब्रिटिश विरोधी प्रचार प्रसार कर लोगों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनप्रतिरोध को प्रेरित करना।
- ❖ वर्ष 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नागरिक स्वतंत्रता तथा नैतिक राजनीति के प्रबल पक्षधर रहे। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक आंदोलनों पर एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा।

बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन (संशोधन) नीति, 2025

चर्चा में क्यों ?

बिहार सरकार ने निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन नीति 2023 को संशोधित करते हुए बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन (संशोधन) नीति, 2025 प्रस्तुत की है।

- ❖ संशोधित नीति का उद्देश्य जैव ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में राज्य की प्रगति में तेज़ी लाना है।

मुख्य बिंदु

- ❖ बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2023 के बारे में:
 - बिहार सरकार ने अपनी पिछली इथेनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2021 को विस्तार देते हुए बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2023 का शुभारंभ किया, ताकि इथेनॉल से आगे बढ़कर संपीड़ित जैव-गैस (CBG)/जैव-CNG इकाइयों को भी सम्मिलित किया जा सके।
 - यह नीति कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर तथा अपशिष्ट का उपयोग करते हुए जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रोज़गार सृजन करना तथा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के साथ संरेखण स्थापित करना है।
- ❖ उद्देश्य:
 - इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के तहत सभी अनुमत फीडस्टॉक्स से 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल और CBG/बायो-CNG का उत्पादन संभव बनाना है तथा बिहार में इन जैव ईंधनों हेतु ग्रीनफील्ड स्टैंडअलोन इकाइयों को बढ़ावा देना है।
- ❖ कवरेज:
 - नीति में वे इकाइयाँ शामिल हैं जो:
 - ❑ 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल (एकल या दोहरी फीड) का उत्पादन करती हैं।
 - ❑ संपीड़ित जैव-गैस (CBG)/जैव-CNG का उत्पादन करती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ प्रोत्साहन:

- यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) की पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
- SC, ST, EBC, महिलाएँ, विकलांग, युद्ध विधवाएँ, एसिड अटैक पीड़ित तथा तीसरे लिंग के उद्यमियों के लिये यह सब्सिडी 15.75% या 5.25 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) निर्धारित की गई है।

❖ बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्द्धन (संशोधन) नीति, 2025 में प्रमुख परिवर्तन

- भूमि पट्टा: अब BIADA-प्रबंधित औद्योगिक भूमि का 25% हिस्सा CBG इकाइयों को पट्टे पर दिया जा सकता है। यह पट्टा 75,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक दर पर 30 वर्षों के लिये होगा।
- तिथि विस्तार: CBG इकाइयों हेतु चरण-1 मंजूरी की अंतिम तिथि एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाई गई है।
- CBG परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति की समय-सीमा 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार निजी निवेशकों तथा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर लागू होगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

चर्चा में क्यों ?

बिहार, स्कैन-एंड-शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण दर हासिल करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।

- ❖ वर्ष 2021 से ABDM के तहत हुए 11.38 करोड़ ओपीडी पंजीकरण में से अकेले बिहार में 2.94 करोड़ पंजीकरण किये गये हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.25 करोड़) और आंध्र प्रदेश (1.70 करोड़) का स्थान है।

मुख्य बिंदु

❖ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में:

- लॉन्च: इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो स्वास्थ्य डाटा के सुरक्षित, कुशल तथा समावेशी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करता है, साथ ही देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, समानता तथा समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है।
- बजट आवंटन: इसे 2021-22 से 2025-26 तक 1,600 करोड़ रुपये के पाँच वर्षीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

❖ ABDM के प्रमुख घटक:

- ABHA नंबर (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता):
 - ABHA ऐप उपयोगकर्ताओं को ABHA पता बनाने, अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करने तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य डाटा साझा करने के लिये सहमति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
- ABHA मोबाइल ऐप (व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड - PHR):
 - यह ABHA पते बनाने और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है।
 - यह उपयोगकर्ताओं को डाटा साझा करने के लिये अपनी सहमति प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR):

- यह सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- इससे योग्य सेवा प्रदाताओं तक आसान पहुँच संभव हो जाती है।

● स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR):

- यह सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डाटाबेस है।
- यह सेवा समन्वय तथा प्रणाली एकीकरण में सुधार करता है।

◆ डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ:

- मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संगृहीत किया जाता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और कागज़ी कार्यवाही कम हो जाती है।
- नुसखों, नैदानिक परिणामों तथा उपचार के इतिहास तक वास्तविक समय पर पहुँच, रोगी की सहमति से भविष्य की यात्राओं के दौरान अस्पताल की प्रक्रियाओं में तेज़ी तथा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

बिहार ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

बिहार **शहरी स्थानीय निकाय चुनावों** के लिये **ई-वोटिंग प्रणाली** शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

- ◆ बिहार **राज्य निर्वाचन आयोग** द्वारा **C-DAC** के सहयोग से विकसित दो मोबाइल एप्लिकेशन “**E-Voting SEBHR**” तथा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप के माध्यम से इस डिजिटल वोटिंग पद्धति को लागू किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

◆ ई-वोटिंग प्रणाली:

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में मतदान केंद्रों पर ई-वोटिंग मशीनों या कियोस्क का उपयोग शामिल हो सकता है, जो तत्काल वोट रिकॉर्ड करती हैं तथा बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के रसीद प्रदान करती हैं।

◆ भारत में अपनी तरह की पहली पहल:

- बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने नगरपालिका तथा शहरी निकाय चुनावों के लिये ई-वोटिंग प्रणाली को अपनाया है।
- एस्टोनिया, वर्ष 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश था।

◆ तकनीकी विशेषताएँ:

- यह प्रणाली ब्लॉकचेन सुरक्षा तथा **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण** जैसे लाइवनेस डिटेक्शन तथा फेस मैचिंग के माध्यम से छेड़छाड़ रहित मतदान सुनिश्चित करती है।
- बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने मतदाता सत्यापन के लिये **फेस रिकग्निशन सिस्टम**, वोटों की गिनती और परिणामों के लिये **OCR तकनीक** तथा **ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स** हेतु डिजिटल ताले जैसी डिजिटल नवाचारों की शुरुआत की है।

◆ महत्त्व:

- समावेशी मतदान: ई-वोटिंग से प्रवासी, दूरदराज़ के मतदाता, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति कहीं से भी मतदान कर सकते हैं।

- ◆ मतदाता में वृद्धि: यह पहल मतदान को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाकर मतदान प्रतिशत में वृद्धि करेगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का इतिहास::

- ❖ 1977: मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के प्रयोग का प्रस्ताव रखा।
- ❖ 1980-81: इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा EVMs का विकास एवं प्रदर्शन किया गया।
- ❖ 1982-83: पहली बार केरल के पुरर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर EVMs का प्रयोग किया गया, तत्पश्चात 8 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में इनका उपयोग किया गया।
- ❖ 1984: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन आवश्यक है, अतः EVMs के प्रयोग पर रोक लगाई गई।
- ❖ 1988: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर 15 मार्च 1989 से EVMs के उपयोग को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।
- ❖ 2013: चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन कर वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की व्यवस्था लागू की गई ताकि पारदर्शिता को और बढ़ाया जा सके।
- ❖ VVPATs का पहली बार उपयोग नागालैंड की 51-नोकसेन विधानसभा क्षेत्र की उपचुनाव में किया गया।
- ❖ 2018: सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेट पेपर की वापसी की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों ?

- ❖ साहित्य अकादमी, जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य संस्था है, ने वर्ष 2025 के लिये अपने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है।
- ❖ मैथिली भाषा के लिये नेहा झा मणि को उनके काव्य संग्रह “बनारस आ हम” के लिये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ प्रमुख विजेता:
 - ❖ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025:
 - ❖ अंग्रेज़ी: अद्वैत कोतारी को उपन्यास “सिद्धार्थ: द बॉय हू बिकेम द बुद्ध” के लिये।
 - ❖ हिंदी: पार्वती तिकी को “फिर उगना” (कविता संग्रह) के लिये।
 - ❖ उर्दू: नेहा रुबाब को उपन्यास “मज़हरुल हक़: तहरीक-ए-आज़ादी-ए-हिंद: हिंद का फ़रामोश करदह क़ायद” के लिये।
 - ❖ बाल साहित्य पुरस्कार:
 - ❖ अंग्रेज़ी: नितिन कुशलप्पा एमपी को “दक्षिण: साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड” के लिये।
 - ❖ हिंदी: सुशील शुक्ल को “एक बातें बारा” के लिये।
 - ❖ मैथिली: मुन्नी कामत को “चुक्का” (बाल कहानियों का संग्रह) के लिये।
 - ❖ उर्दू: गज़नफर इकबाल को “क्रौमी सितारे” (लेख संग्रह) के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



साहित्य अकादमी के बारे में:

❖ स्थापना:

- 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

❖ उद्देश्य:

- भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना।

❖ भाषाएँ:

- 24 भारतीय भाषाओं में कार्य, जिनमें सभी 22 संवैधानिक भाषाएँ, तथा अंग्रेज़ी और राजस्थानी शामिल हैं।

❖ गतिविधियाँ:

- पुस्तकें, पत्रिकाएँ, शब्दकोश और विश्वकोश प्रकाशित करता है, अब तक 6000 से अधिक पुस्तकें; लगभग हर 19 घंटे में एक नई पुस्तक।
- भारत और विदेशों में प्रति वर्ष लगभग 300 सेमिनार, कार्यशालाएँ तथा साहित्यिक बैठकें आयोजित करता है।
- अनुवाद केंद्र और अभिलेखागार चलाता है; जनजातीय और मौखिक साहित्य को बढ़ावा देता है।
- 24 वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार, 24 अनुवाद पुरस्कार, भाषा सम्मान, फेलोशिप तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रदान करता है।

साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार

- परिचय: इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष उन उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है, जो 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिये लिखी गई हों। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में दिये जाते हैं।

- पुरस्कार के घटक: 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, उत्कीर्ण पट्टिका (प्लाक), एक शॉल और प्रशस्ति पत्र।

❖ पात्रता मानदंड:

- कृति मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिये तथा पिछले 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई हो।
- किसी भाषा में पुरस्कार पर विचार करने हेतु कम से कम 3 पात्र पुस्तकें होनी चाहिये।
 - पौराणिक कथाओं के रूपांतरण स्वीकार्य हैं।
 - मरणोपरान्त कृतियाँ पात्र हैं यदि लेखक का निधन उस 5-वर्षीय अवधि के भीतर हुआ हो।
- अनुवाद, संकलन, संक्षेपण, शोध-प्रबंध तथा साहित्य अकादमी के बोर्ड सदस्यों, फेलो (Fellows) या भाषा सम्मान प्राप्तकर्ताओं की कृतियाँ अपात्र मानी जाती हैं।

साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार

❖ परिचय

- इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में उन युवा भारतीय लेखकों (35 वर्ष या उससे कम आयु) को सम्मानित करने के लिये की गई थी, जिन्होंने 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में मौलिक साहित्यिक कृतियाँ प्रस्तुत की हों।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- केवल अकादमी पुरस्कार ही आत्म-नामांकन तथा प्रकाशक नामांकन के लिये खुले होते हैं।
- इसमें 50,000 रुपए की नकद राशि, एक पट्टिका, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र शामिल होते हैं।

❖ पात्रता:

- लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिये तथा पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिये।
- कृति मौलिक होनी चाहिये, अनुवाद, संक्षिप्तीकरण, शोधप्रबंध या पहले से पुरस्कृत कृति नहीं होनी चाहिये।
- मरणोपरांत कृतियाँ स्वीकार नहीं की जाती।
- भाषा में न्यूनतम तीन पात्र पुस्तकों की उपलब्धता अनिवार्य है।

बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

बिहार भारत के उन पहले छह राज्यों में शामिल होगा, जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा।

मुख्य बिंदु

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में

❖ घोषणा और अनुमोदन:

- पटना में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की पाँचवीं बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री ने यह घोषणा की कि बिहार में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
- इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो पूर्वी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

❖ बिहार के लिये महत्व:

- इस परियोजना के माध्यम से राज्य में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन तथा तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। \
- विद्युत की कमी और सीमित आधारभूत संरचना से जुड़ी बिहार की पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए यह कदम इसके ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है।

परमाणु ऊर्जा मिशन

❖ महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार:

- इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट (30 जनवरी 2025 तक) से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट करना है, जिससे परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया जा सके तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन मिल सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर ध्यान:

- यह मिशन 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देता है।

● इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किये गए SMR को विकसित और संचालित करना है, जिससे दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।

♦ प्रत्येक राज्य में संयंत्र:

- इस मिशन के अंतर्गत भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

♦ निजी क्षेत्र की भागीदारी:

- निजी निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन के लिये विधायी परिवर्तन की योजना बनाई गई है।
- इससे परमाणु परियोजनाओं की तीव्र स्थापना, नवाचार और आर्थिक विकास को सहायता मिलेगी, क्योंकि निजी संस्थाएँ भूमि, पूंजी और वित्तपोषण का योगदान देंगी जबकि NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) रिएक्टर परिचालन का प्रबंधन करेगी।

लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):

- SMR एक उन्नत परमाणु रिएक्टर है, जिसकी क्षमता 300 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक रिएक्टरों की क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
- यह तकनीक उन्नत, लागत प्रभावी तथा सुरक्षित है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है, जहाँ मध्यम विद्युत माँग होती है या बड़े संयंत्रों की स्थापना संभव नहीं है।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), बंद हो रहे कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को पुनः उपयोगी बनाने तथा दूरदराज़ के क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये SMR पर कार्य कर रहा है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भी भारत के विशाल थोरियम संसाधनों के उपयोग के लिये हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च तापमान गैस-शीतित रिएक्टरों तथा पिघले हुए नमक रिएक्टरों जैसे रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विद्युत क्षेत्र में अन्य हालिया घटनाक्रम

♦ बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएँ:

- परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने बिहार में 1,000 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता की परियोजना को मंजूरी दी है।
- यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करेगी तथा ग्रिड स्थिरता को बढ़ाएगी, जिसमें प्रति मेगावाट 18 लाख रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि शामिल होगी।

♦ BESS परियोजना की आधारशिला:

- प्रधानमंत्री ने 20 जून 2025 को सिवान में 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना की आधारशिला रखी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ बिहार को अतिरिक्त सहायता:

- गर्मियों में उच्च विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केंद्र ने आगामी 3 से 6 महीनों के लिये बिहार को अतिरिक्त 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने पर सहमति दी है।

❖ स्मार्ट मीटर और घाटा नियंत्रण:

- राज्य को 8 मिलियन स्मार्ट मीटर स्थापित करने तथा तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में उल्लेखनीय कमी लाने के लिये सराहना मिली है, जो विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।

बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण कल्याण पहल को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

बिहार मंत्रिमंडल ने गाँव के बुनियादी ढाँचे, सामाजिक पेंशन, महिला उद्यमिता, सब्सिडी वाले भोजन तथा मजबूत स्थानीय शासन और कल्याण उपायों को मंजूरी प्रददी है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **जीविका दीदी की रसोई का संचालन:** मंत्रिमंडल ने किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रखंड स्तर के कार्यालयों, उप-मंडल तथा जिला मुख्यालयों पर जीविका दीदी की रसोई इकाइयों के संचालन को मंजूरी दी है।
 - यह पहल अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों तक विस्तारित की जाएगी, जहाँ 5 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के तहत रियायती भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- ❖ **वित्तीय सहायता:** हाल ही में सम्पन्न जाति-आधारित सर्वेक्षण में चिह्नित 94 लाख आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इसके लिये मानदंड निर्धारित करेगी।
- ❖ **पेंशन में वृद्धि:** मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा विधवाओं हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके तहत मासिक पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 कर दी गई है।
- ❖ **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिये व्यय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
- ❖ **पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिये भत्ते:** त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा ग्राम कचहरी के सदस्यों को दिये जाने वाले भत्तों में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है।
- ❖ **अनुग्रह राशि:** पंचायत या ग्राम कचहरी के सदस्य की कार्यकाल के दौरान प्राकृतिक मृत्यु होने पर, उनके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
- ❖ **विवाह हॉल निर्माण:** प्रत्येक विवाह हॉल का निर्माण 50 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा और इसे वर्तमान वित्त वर्ष से आरंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना

जीविका:

- जीविका, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिसका उद्देश्य बिहार में ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण करना है।
- यह परियोजना बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन सोसाइटी (BRLPS) द्वारा प्रबंधित की जाती है, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
 - इस परियोजना को प्रारंभ में विश्व बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त था तथा बाद में इसे बिहार कोसी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना (BKFRP) के अजीविका पुनर्स्थापन घटक को सम्मिलित करते हुए विस्तारित किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की रणनीतियों को लागू करने हेतु BRLPS को बिहार राज्य के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के रूप में नामित किया गया है।

दीदी की रसोई पहल:

- केरल के कुडुम्बश्री मॉडल से प्रेरित यह पहल वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिहार में सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है।
- यह बिहार परिवर्तनकारी विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा समर्थित है तथा BRLPS (जीविका) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
- इसका पहला केंद्र वैशाली में स्थापित किया गया था और वर्तमान में बिहार के 38 जिलों में 83 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तथा स्कूल शामिल हैं।
- इस पहल के अंतर्गत 1,200 से अधिक महिला उद्यमियों तथा 150 पूर्णकालिक कर्मचारियों को रोजगार मिला है, जिन्हें होटल प्रबंधन और खानपान विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है।
- महिला उद्यमियों को जीविका द्वारा संचालित 7-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता, लेखांकन तथा ग्राहक सेवा में प्रशिक्षित किया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

